राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को ऋण

2254. **श्री ईश दत्त यादव :**
श्री नागमणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण की प्रतिशतता निर्धारित करने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कृषि क्षेत्र को बैंकों से निर्धारित प्रतिशतता तथा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान कृषि क्षेत्र की आर्थिक आवश्यकताएं क्या रहीं और उक्त अवधि के दौरान बैंकों द्वारा उन्हें कितने प्रतिशत ऋण प्रदान किया गया; और

(ङ) कृषि क्षेत्र को आवश्यकतानुसार ऋण सुविधा में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा अब कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं/ उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने निवल बैंक ऋणों का 18% कृषि क्षेत्र को देना अपेक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में पिछले तीन वर्षों के लिए कृषि क्षेत्र को अग्रिमों का कुल प्रवाह तथा निवल बैंक ऋणों की तुलना में उसकी प्रतिशतता निम्नानुसार है :

के प्रतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	कृषि को कुल अग्रिम (करोड़ रुपए)	निवल बैंक ऋणों की तुलना में कुल कृषि अग्रिमों की प्रतिशतता
मार्च, 95	15038.45	14.00
मार्च, 96	16832.04	14.51
मार्च, 97	19741.21	16.64

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में ऋण की अनुमानित आवश्यकता और उसकी तुलना में वास्तविक बुनियादी वितरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कुल अनुमानित आवश्यकता	सभी एजेंसियों से कृषि क्षेत्र को बुनियादी ऋण का वास्तविक प्रवाह
1994-95	26669	18744
1995-96	30490	22032
1996-97	34890	28653 (आंकड़े अनन्तिम)

(ङ) कृषि क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए संस्थागत व्यवस्था के संबंध में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं : अगले पांच वर्षों में नाबार्ड की शेयर पूंजी को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए करना, आधारभूत परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए ग्रामीण आधारिक विकास निधि की स्थापना करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिए, चालू वर्ष के दौरान 270 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन, वाणिज्यिक और उच्च तकनीक वाली कृषि

में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय कृषि विकास वित्त कम्पनियों की स्थापना करना और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को स्थापना करना ।

Beneficiaries of Bank Securities Scam

2255. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the real beneficiaries of the bank securities scam;

(b) the amount of recovery of the huge losses from those who had played the fraud; and

(c) what happened to the arrears of a few thousand crores of rupees due for payment as income tax by Harshad Mehta and others?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) and (b) In terms of the provisions of the Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Act, 1992, the assets of 47 persons/entities presently stand attached with the Custodian. These assets are valued at Rs. 3037.40 crores as on July, 1997. The disposal of these assets is required to be made as per the provisions of law and the orders of the Special Court.

(c) The realisation of income tax demands of the Income Tax Department against notified persons/entities through disposal of attached assets has to be made as per orders of the Special Court, Bombay/Supreme Court. The Office of the Custodian has reported that Rs. 251.70 crores towards tax (excluding interest/penalty) have so far been released by the Custodian under the orders of both the Supreme Court and Special Court, Bombay.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा

2256. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जमाराशि और निवेश का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त बैंक कब तक कार्य करना प्रारम्भ करेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्रियाकलापों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है । इसके अतिरिक्त, उनके परिचालनों की राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है ।

वर्ष 1993–94, 1994–95 और 1995–96 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशियों और निवेशों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(लाख रुपए में)

वर्ष	जमाराशियां	निवेश
1993–94	246276.33	11755.60
1994–95	301660.62	57544.33
1995–96	380687.17	96609.03